



THE
EAST INDIA COMPANY.

OF A
THEBREST
OF THE
EAST INDIA COMINCTION
OF THE
TO RIUSIES.

मद्रास संकट (1809): नागरिक सर्वोच्चता बनाम सैन्य विशेषाधिकार

ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर एक संस्थागत विद्रोह का
'शाही दस्तावेज़' (Imperial Dossier)

अपराधशास्त्रीय अंतर्दृष्टि
द्वारा
डॉ. मृदुल श्रीवास्तव

वर्गीकरण: अति गोपनीय
(Highly Confidential)
विषय: मद्रास प्रेसीडेंसी के सैन्य
असंतोष के कारण

LONDON:
Printed & respec of EAST INDIA COKEET, B.H.
ASTROED, OF THE ARMYARE,
1810.

मद्रास प्रेसीडेंसी में सैन्य असंतोष (1807-1809): विद्रोह के कारण और घटनाक्रम

यह इन्फोग्राफिक 1810 के एक ऐतिहासिक वृत्तांत पर आधारित है, जो मद्रास प्रेसीडेंसी में सेना और नागरिक सरकार के बीच बढ़ते तनाव का विवरण देता है। यह मुख्य रूप से आर्थिक कटौतियों और प्रशासनिक परिवर्तनों से उत्पन्न उस विवाद को दर्शाता है जिसने ब्रिटिश शासन को संकट में डाल दिया था।

असंतोष के मुख्य कारण (Primary Causes of Discontent)

टेंट कॉन्ट्रैक्ट (Tent Contract) की समाप्ति



टेंट कॉन्ट्रैक्ट (Tent Contract) की समाप्ति

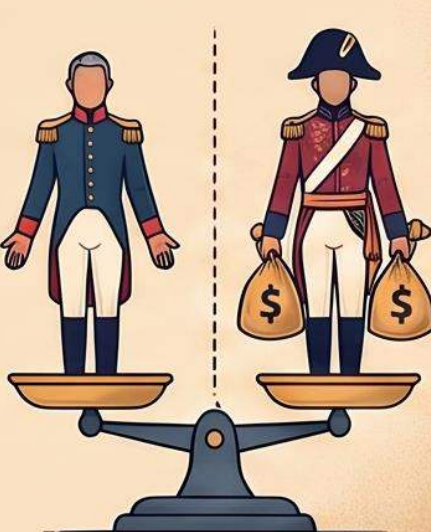
अधिकारियों के तंबू भत्ते को खत्म करना विद्रोह का सबसे बड़ा और तत्काल कारण बना।

बाज़ार भत्ते (Bazar Allowance) पर रोक



बाज़ार भत्ते (Bazar Allowance) पर रोक सैन्य स्टेशनों के बाज़ारों से होने वाली आय को अधिकारियों के लिए बंद कर दिया गया।

मद्रास बनाम बंगाल भत्ता असमानता



मद्रास बनाम बंगाल भत्ता असमानता मद्रास के अधिकारियों ने बंगाल सेना के समान वेतन और भत्तों की मांग की थी।

घटनाक्रम और बढ़ता संकट (1807-1809)

1807: सुपारों की शुरुआत



1807: सुपारों की शुरुआत

सर जॉन कैडॉक ने सैन्य खर्चों में कटौती के लिए कड़े प्रशासनिक सुधार लागू किए।



कमांडर-इन-चीफ का अपमान

जनरल मैकडॉवल को सरकारी काउंसिल में स्थान न देना सेना के लिए अपमानजनक माना गया।

1809: गिरफ्तारी और खुला विद्रोह



1809: गिरफ्तारी और खुला विद्रोह

ववार्टर-मास्टर जनरल की गिरफ्तारी ने सरकार और सेना के बीच सीधा संघर्ष पैदा किया।

आर्थिक सुधार (1808) और प्रभाव/परिणाम

आर्थिक सुधार (1808)

प्रभाव/परिणाम

टेंट कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति



अधिकारियों में भारी वित्तीय नुकसान और गुस्सा



बाज़ार शुल्क उन्मूलन



कमांडिंग अधिकारियों के व्यक्तिगत लाभ पर रोक



बंगाल समान भत्ता मांग



सरकार द्वारा "राजद्रोह के समान" मानकर खारिज

संकट की जड़: युद्ध और वित्तीय घाटा

**निरंतर युद्ध
(1799-1805)**

टीपू सुल्तान और मराठों
के खिलाफ लॉर्ड वेलेस्ली
(Lord Wellesley) के
सैन्य अभियान।

**भारी कर्ज
(The Indian Debt)**

बंगाल के संसाधनों पर
भारी दबाव।
मद्रास प्रेसीडेंसी में गंभीर
वित्तीय घाटा।

**सुधार का आदेश
(1807)**

लंदन और बंगाल (लॉर्ड
मिंटो) से 'खर्च में कटौती'
के सख्त निर्देश।
नागरिक और सैन्य खर्चों की
गहन समीक्षा की शुरुआत।

साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन अब कोई बाहरी राजा नहीं,
बल्कि कंपनी का अपना 'कर्ज' था।

सत्ता का हस्तांतरण: तलवार से कानून की ओर

पूर्व व्यवस्था

- **सैन्य जागीरदारी (Military Tenure):** सैन्य अधिकारी ही नागरिक और प्रशासनिक अधिकार चलाते थे।
- **स्वायत्तता:** 40-50 छोटे सैन्य कमांड, जहां जनरलों का पूर्ण नियंत्रण था।
- **अव्यवस्था:** न्याय प्रणाली कमजोर, संपत्ति के अधिकार अपरिभाषित।

“सेना के लिए यह शक्ति छिन जाना एक बड़ा झटका था। वे अब शासक नहीं, केवल कर्मचारी थे।”

लॉर्ड कॉर्नवॉलिस के सुधार

- **नागरिक सर्वोच्चता (Civil Authority):** अदालतों (Courts of Judicature) और नियमित सरकार की स्थापना।
- **केंद्रीकरण:** छोटे कमांड्स को 5-6 बड़े कमांड्स में समेटने का आदेश।
- **कानून का शासन:** नागरिक अधिकारियों का सैन्य अधिकारियों पर नियंत्रण।

वैचारिक टकराव: दो गुटों का विश्लेषण

	नागरिक सरकार (लॉर्ड बेंटिंक / सर जॉर्ज बालो)	सैन्य नेतृत्व (जनरल मैकडॉवल / सैन्य अधिकारी)
मूल उद्देश्य	लंदन के आदेशानुसार वित्तीय घाटे को कम करना और व्यवस्था स्थापित करना।	अपनी प्रतिष्ठा, आय और बंगाल सेना के समान दर्जे की रक्षा करना।
भत्ते पर विचार	भत्ते केवल आर्थिक और सार्वजनिक कारणों से हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं।	भत्ते उनका 'अधिकार' हैं और कटौती उनके सम्मान पर चोट है।
नियंत्रण	सैन्य शक्ति को नागरिक सरकार के अधीन होना चाहिए।	सैन्य मामलों में सरकार का हस्तक्षेप अवांछनीय है।

'टेंट अनुबंध' (The Tent Contract) का भ्रमजाल

1802 में शुरू की गई एक व्यवस्था जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई...

शांतिकाल (Peacetime)

सरकार कमांडरों को मासिक 'टेंट भत्ता' देती है

युद्ध न होने के कारण टेंट और जानवरों का खर्च बचता है



परिणाम: कमांडर सारा पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं (भारी मुनाफा)।

युद्धकाल (Wartime)

अचानक युद्ध की घोषणा (जैसे मराठा युद्ध)

कमांडरों के पास टेंट ले जाने के लिए मवेशी और उपकरण नहीं हैं

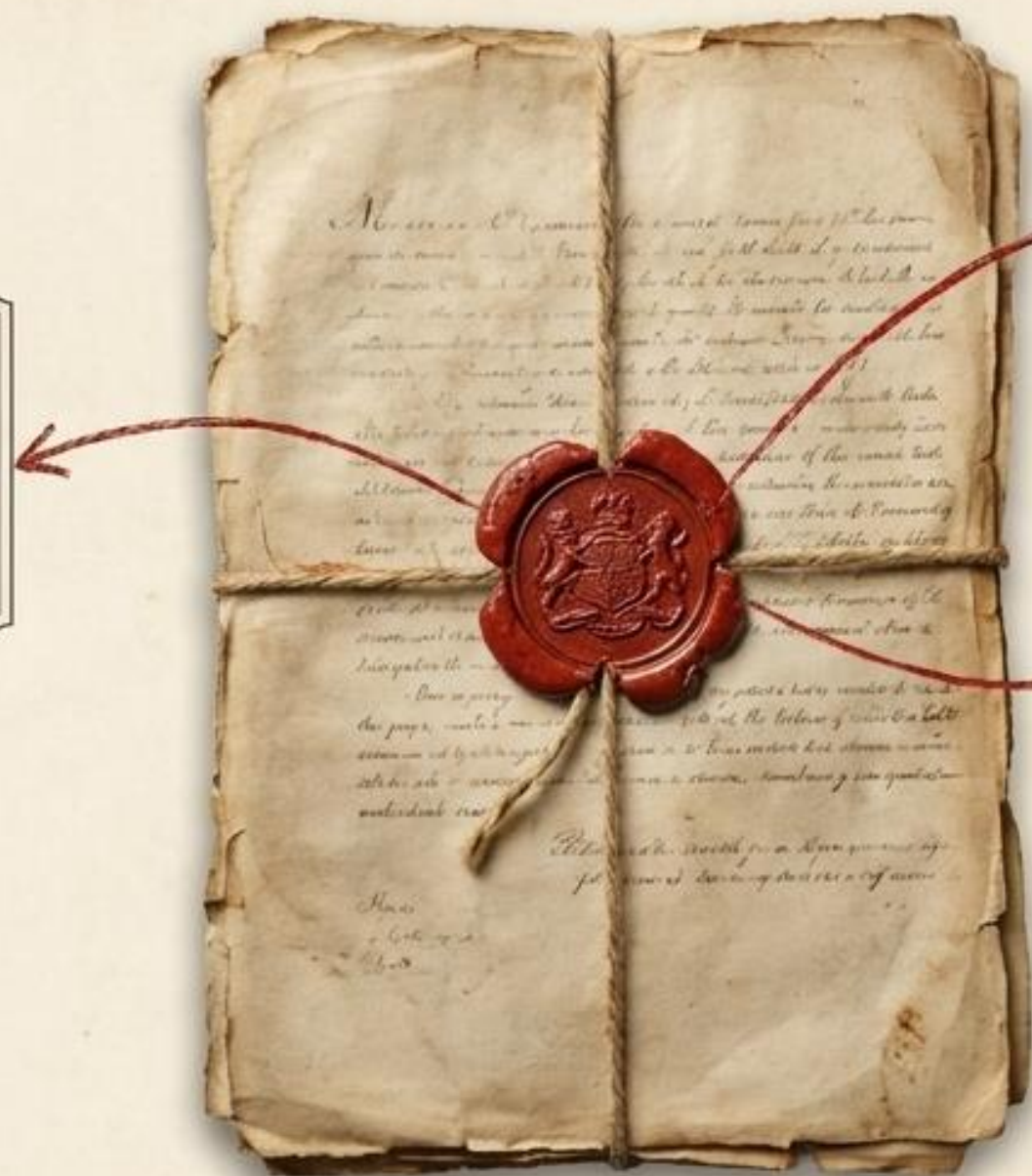


परिणाम: सेना की गति धीमी, तोपखाना पीछे छूटा, अभियान खतरे में।

निष्कर्ष: यह अनुबंध अर्थव्यवस्था के लिए बनाया गया था, लेकिन यह कमांडरों के 'व्यक्तिगत भरण-पोषण' का साधन बन गया।

चिंगारी: क्वार्टर-मास्टर जनरल (QMG) की रिपोर्ट

समीक्षा का आदेश: कमांडर-इन-चीफ के आदेश पर QMG ने टेंट अनुबंध की जांच की।



रिपोर्ट का निष्कर्ष: QMG ने स्पष्ट किया कि टेंट अनुबंध प्रणाली 'खर्चीली और अक्षम' है। उन्होंने सार्वजनिक खर्च पर टेंट आपूर्ति की पुरानी व्यवस्था (Public Expense System) वापस लाने की वकालत की।

मई 1808 का आदेश: सुप्रीम गवर्नमेंट (मद्रास) ने QMG की रिपोर्ट के आधार पर टेंट अनुबंध को पूरी तरह समाप्त कर दिया।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया: मद्रास के कमांडरों ने इसे अपने 'चरित्र और सम्मान पर सीधा हमला' माना। उन्हें लगा कि QMG ने उन पर पैसे गबन करने का अप्रत्यक्ष आरोप लगाया है।

नेतृत्व की विफलता: जनरल मैकडॉवल का अहंकार



परिषद से निष्कासन (Seat in Council)

- पूर्व कमांडरों के विपरीत, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने नए कमांडर-इन-चीफ, जनरल मैकडॉवल को 'मद्रास परिषद' में सीट नहीं दी।
- मैकडॉवल ने इसे अपना व्यक्तिगत अपमान माना और सार्वजनिक रूप से सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त किया।

कर्तव्य बनाम भावना

- एक सर्वोच्च सैन्य अधिकारी के रूप में उनका कर्तव्य सेना में अनुशासन बनाए रखना था।
- लेकिन अपने व्यक्तिगत अपमान के कारण, मैकडॉवल ने 'मूक दर्शक' (Passive Line) बने रहना चुना।
- उन्होंने जानबूझकर अधिकारियों के बीच पनप रहे असंतोष और गुटबाजी को अनदेखा किया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसे बढ़ावा दिया।

‘बंगाल समानता’ (Bengal Parity) की मांग

मद्रास सेना

- टेंट और बाज़ार भत्ते छीने गए।
- वेतन और भत्ते बंगाल की तुलना में कम।
- जीवन यापन और यूरोपीय वस्तुओं की उच्च कीमतें।



बंगाल सेना (The King's & Company's Troops)

- 'पूर्ण भत्ता' (Full Batta) प्राप्त।
- सर्वोच्च वेतन और विशेषाधिकार।
- ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पसंदीदा सैन्य इकाई।

अपील का प्रसार: मई 1808 में, सैन्य छावनियों (जैसे हैदराबाद) में गुप्त रूप से पत्र (Circular Letters) बांटे गए। मांग थी कि मद्रास सेना को भी बंगाल सेना के समान 'पूर्ण भत्ता और टेंट भत्ता' दिया जाए। यह सैन्य अनुशासन का सीधा उल्लंघन था।

विद्रोह की सीढ़ियां (The Path to Insubordination)

सीधा हमला (Direct Attack)

24 सैन्य कमांडरों द्वारा क्वार्टर-मास्टर जनरल (QMG) के खिलाफ 'चरित्र हनन' का आरोप लगाते हुए औपचारिक चार्जशीट दाखिल करना।

आधिकारिक मौन (Official Complicity)

जनरल मैकडॉवल का सेना के इस कृत्य को रोकने से इनकार करना और सरकार के आदेशों की अवहेलना करना।

अवैध पत्राचार (Circular Letters)

पूरे मद्रास में कमांडरों द्वारा बिना अनुमति के हस्ताक्षर अभियान चलाना और सुप्रीम गवर्नमेंट को सीधे याचिकाएं भेजने की योजना बनाना।

सुगबुगाहट (Whispers)

अधिकारियों के बीच असंतोष; टेंट अनुबंध और बाज़ार भत्ते खत्म होने पर निजी शिकायतें।

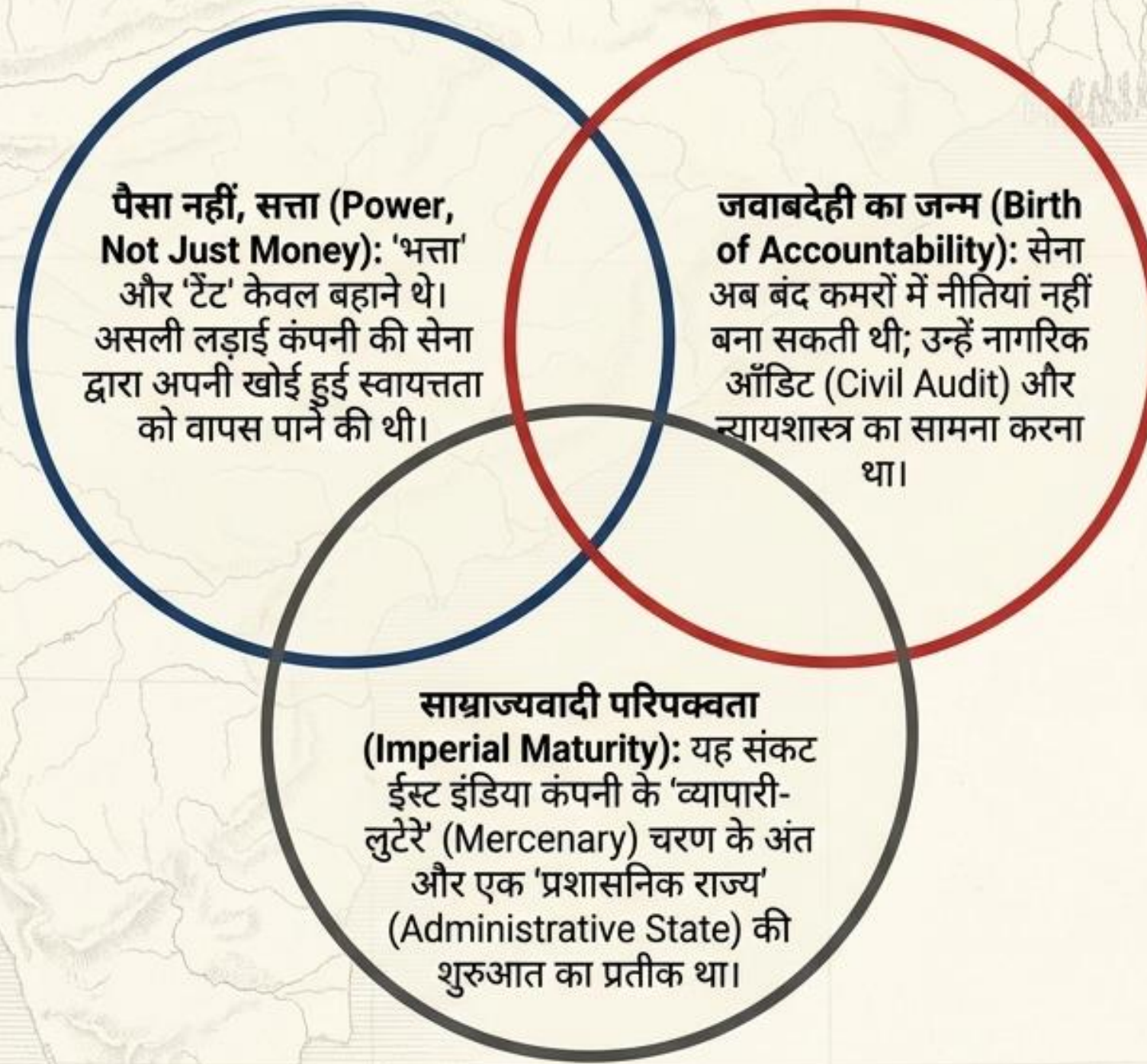
चरम बिंदु: QMG की गिरफ्तारी (जनवरी 1809)



- 20 जनवरी 1809: इंग्लैंड लौटने से ठीक पहले, जनरल मैकडॉवल ने अप्रत्याशित रूप से क्वार्टर-मास्टर जनरल को 'गिरफ्तार' (Under Arrest) कर लिया।
- कारण: 24 अधिकारियों के दबाव में, जिन्होंने QMG की टेंट अनुबंध रिपोर्ट को अपना अपमान माना था।
- नागरिक सरकार का हस्तक्षेप: जज एडवोकेट जनरल (Judge Advocate General) ने इस चार्ज को पूरी तरह 'अवैध और अन्यायपूर्ण' घोषित किया।

सुधार को दंडित नहीं किया जा सकता: सरकार ने स्पष्ट किया कि एक अधिकारी (QMG) को अपने वरिष्ठों के आदेश पर किए गए आधिकारिक कर्तव्य के लिए सजा नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा हुआ, तो 'भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला हर सुधार हमेशा के लिए रुक जाएगा।'

निष्कर्ष: एक व्यवस्था का दर्दनाक अंत



मद्रास का संकट केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि यह आधुनिक प्रशासनिक भारत के निर्माण की सबसे भयानक प्रसव-पीड़ा (Labor Pain) थी।